



एक भारत श्रेष्ठ भारत

सबका साथ
सबका विकास

चुनाव
घोषणा
पत्र
2014
मुख्य
बिन्दु



भारतीय जनता पार्टी

प्रस्तावना

आज भारत को 'डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड' के रूप में दुर्लभ क्षमताओं और अवसरों का वरदान मिला हुआ है। अगर हम मजबूती देने और इनका सदुपयोग करने में सक्षम हुए, तो हम उन ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं, जिनका भारत सही में हकदार है। आज देश की बदहाली की सबसे बड़ी वजह उन लोगों के बुरे इरादे हैं, जिनका 60 वर्षों से देश पर शासन चल रहा है। और यही हम पहला बदलाव लाएंगे। भाजपा की नीतियों और उनके क्रियान्वयन का पहला लक्ष्य होगा : "एक भारत श्रेष्ठ भारत" और हमारा रास्ता होगा। "सबका साथ—सबका विकास"। यही राष्ट्र और देशवासियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। पार्टी के इस संकल्प के साथ, श्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में हम 16वीं लोकसभा के चुनाव में उत्तर रहे हैं। और हम पूरे मनोयोग से भारत को स्थायी सशक्त, दूरदृष्टियुक्त और विकास और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध सरकार देने के लिए काम करेंगे।

यह अपने और अपने देश का भाग्य बदलने का अवसर है।

क्या करना चाहती है भाजपा देश की जनता के लिए ?

देश के कोने-कोने को विकास से जोड़ना

- 100 नए शहर बसाना।
- देश के 100 सबसे पिछड़े जिलों को विकसित करके उन्हें अन्य विकसित जिलों के समकक्ष बनाना।
- प्रत्येक व्यक्ति का अपना घर हो जिसमें बिजली, पानी तथा शौचालय की सुविधा सुलभ हो।
- देश भर के गांवों के विकास के लिए ग्रामीण हाट का जाल बिछाना और गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया करना।
- कुटीर और छोटे उद्योगों में कार्यरत परंपरागत कारीगरों को अपनी क्षमताओं का विकास हेतु ऋण सुविधा और बाजार से जुड़ाव स्थापित करने में मदद देना।
- एक व्यापक राष्ट्रीय ऊर्जा नीति का निर्माण करना।
- मनरेगा को चालू रखते हुए इसको उत्पादक कार्यों से जोड़ना।
- राष्ट्रीय गैस ग्रिड निर्माण करना।
- राष्ट्रीय वाई-फाई नेटवर्क खड़ा करना।
- बुलेट रेलगाड़ियों की हीरक चर्तुर्भुज परियोजना शुरू करना।
- कृषि उत्पाद वितरण हेतु रेल नेटवर्क बनाना।
- पर्यटन रेल नेटवर्क बनाना।
- हर घर को नल द्वारा पानी की सप्लाई।
- स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ (2022) तक हर परिवार को एक पक्का घर सुनिश्चित करना।

महंगाई पर नियंत्रण

- दाम न बढ़ें इसके लिए अलग से कोष की व्यवस्था ।
- जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने हेतु विशेष अदालतों की स्थापना, अपराधियों को त्वरित दंड व्यवस्था ।
- भारतीय खाद्य निगम को खरीद, भंडारण और विपणन हेतु तीन भागों में बांटना ।

भ्रष्टाचार निर्मूलन के लिए

- इ-गवर्नेंस द्वारा पारदर्शिता को बढ़ावा ।
- प्रशासन और नागरिकों के बीच कार्यप्रणाली में मनमानी के अवसर समाप्त करना ।
- प्रत्येक स्तर पर प्रक्रियाओं और तरीकों को सरलीकृत करना – नागरिकों, संस्थाओं और प्रतिष्ठानों में आपसी विश्वास बढ़ाना ।

रोजगार को बढ़ावा देना

- रोजगार कार्यालयों का कैरियर केंद्रों के रूप में परिवर्तन ।
- उद्यमिता विकास और व्यापक ऋण सुविधा के माध्यम से रोजगार निर्माण ।
- रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु कपड़ा, जूता, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान व पर्यटन को विशेष रूप से बढ़ावा देना ।
- पांच 'प' – परंपरा, प्रतिभा, पर्यटन, पण (व्यापार), और प्रौद्योगिकी की शक्तियों की सहायता से भारत को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना ।

महिलाएं – राष्ट्र निर्माता

- कन्याओं को बचाने और पढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान : **बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ** शुरू करना ।
- बलात्कार पीड़ित व एसिड हमलों की शिकार महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार एक कोष का निर्माण करेगी, ताकि ऐसी महिलाओं के इलाज और उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी के मेडिकल का खर्च उठाया जाए !
- पुलिस स्टेशनों को महिलाओं के अनुकूल बनाया जाएगा और विभिन्न स्तरों पर पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएंगी ।
- महिलाओं के विशेष हुनर प्रशिक्षण के लिए कारोबारी प्रशिक्षण पार्क बनाएं जाएंगे ।
- महिलाओं को विधान सभाओं एवं संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण दिलाने की प्रतिबद्धता ।

एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग – सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण

- भाजपा हर स्तर पर छुआछूत और अस्पृश्यता खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध है ।
- ऐसा वातावरण तैयार किया जाएगा जिसमें एससी/एसटी और ओबीसी वर्ग समेत अन्य गरीब तबकों को प्राथमिकता के आधार पर शिक्षण और उद्योग

लगाने हेतु अवसर मिल सकें।

- भाजपा सुनिश्चित करेगी कि एससी/एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए जिस फंड की व्यवस्था की गई है, उसका समुचित और बेहतर तरीके से उपयोग हो।
- इन वर्गों के लोगों को घर, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक मिशन चलाया जायेगा।

आदिवासियों के लिए घर, पानी, बिजली शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करना और उन्हें विस्थापन से बचाना।

अल्पसंख्यक – समान अवसर

- अल्पसंख्यक शैक्षणिक व्यवस्था और संस्थानों को सशक्त एवं आधुनिक बनाया जाएगा। राष्ट्रीय मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा।

सीमा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान

- उत्तर पूर्वी राज्यों के प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का दोहन कर उन्हें पश्चिमी क्षेत्रों के बराबर ला खड़ा करना।
- उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बनाए गए मंत्रालय का सशक्तिकरण।
- कश्मीरी पंडितों को उनके अपने प्रदेश जम्मू-कश्मीर में ससम्मान वापसी के लिए कदम उठाना और प्रदेश में सुशासन स्थापित करना।
- धारा 370 की समाप्ति।

आतंक के खिलाफ

- आतंकवाद, चरमपंथ और अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किएं जाएंगे।
- सीमापार आतंकवाद और घुसपैठ से पूरी सख्ती से निबटा जायेगा।
- आतंकवाद प्रतिरोधी तंत्र की स्थापना।

वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाना

- वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता।

शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए

- शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक पास करवाना।

युवाओं के लिए

- राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद् का गठन करना।
- विद्यार्थियों को ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
- एक “राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिभा खोज प्रणाली” का प्रारंभ।

भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए

- हर राज्य को एम्स जैसी एक स्वास्थ्य संस्था देना तथा राष्ट्रीय इ-स्वास्थ्य अथॉरिटी का गठन।

टैक्स प्रणाली में सुधार

- टैक्स ढांचे का सरलीकरण करना और उसको न्यायसंगत बनाना।

किसानों के लिए

- किसानों को उनकी लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ मिलना सुनिश्चित करना।
- किसानों के लिए प्रादेशिक टी. वी. चैनल शुरू करना, ए. पी. एम्. सी. एक्ट में सुधार लाना, भूमि उपयोग की राष्ट्रीय नीति का निर्माण और भूमि बीमा योजना लागू करना आदि।

उद्योगों के लिए

- देश भर में उद्योगों, विशेषकर छोटे और मंझोले उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक और बिजली जैसी सुविधाओं को सुलभ बनाना।
- मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं।
- खुदरा विक्रेताओं, छोटे व्यापारों और विक्रेताओं के हितों की रक्षा के लिए सभी जरुरी कदम उठाएं जाएंगे!

गांवों के विकास के लिए

- गांव को हर मौसम के अनुकूल सड़क से जोड़ना।
- प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के तहत – हर खेत को पानी।

असंगठित क्षेत्र के लिए

- असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए पहचान पत्र, श्रमिक बैंक की स्थापना, पेंशन और स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करना।

बुनकर और कारीगरों के लिए विशेष ध्यान

- कारीगर, लुहार, बुनकर, बढ़ई, केश-कर्तक, चर्मकार और कुम्हार आदि के साथ-साथ मछुआरा समुदाय के कौशल विकास व उनके व्यवसाय को अधिक कुशल अवसर प्रदान करने के लिए नई योजनाएं बनाई जाएंगी।

पूर्व सैनिकों के हित में

- पूर्व सैनिकों की तकलीफों की सुनवाई के लिए पूर्व सैनिक आयोग का गठन।
- पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई सी एच एस) में सुधार तथा पूर्व सैनिकों के पुनर्रोजगार इस आयोग के कार्यक्षेत्र होंगे।
- 'एक रैक-एक पेंशन' योजना को लागू करना।

हिमालय

- विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों को समन्वित कर अंतर-सरकारी साझेदारी के अंतर्गत एक अद्भुत और अभूतपूर्व कार्यक्रम "नेशनल मिशन ॲन हिमालय" प्रारंभ करना।
- हिमालय सरक्षण फण्ड की स्थापना।
- हिमालय प्रौद्योगिकी को समर्पित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना।

देश को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले अन्य सार्थक कदम

- सांस्कृतिक महत्व से जुड़ी धरोहरों जैसे हिमालय, मरुस्थल क्षेत्रों तथा प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित 50 पर्यटन सर्किट बनाना।
- क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन तथा सभी भाषाओं के रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन करना।
- एक “राष्ट्रीय हुनर मिशन” स्थापित करना।
- जनसंख्या रिस्थीकरण को एक राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रम के रूप में चालू किया जाएगा।

भारतीय संस्कृति और विरासत की रक्षा

- संविधान के दायरे में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी विकल्पों को तलाशा जाएगा।
- रामसेतु, सेतु—समुद्रम चैनल परियोजना पर निर्णय लेते समय उसके हमारी सांस्कृतिक विरासत का अंग होने और थोरियम भंडार के तथ्यों को दृष्टिगत रखा जाएगा।
- गाय और गौवंश की रक्षा की जाएगी।
- गंगा में निर्मलता व उसके प्रवाह में निरंतरता तथा सभी प्रमुख नदियों की स्वच्छता सुनिश्चित करना।
- सर्वश्रेष्ठ परंपराओं से प्रेरित और संविधान की भावना के अनुसार समान नागरिक संहिता।

व्यवस्थागत सुधार

- प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत एक संस्था का गठन कर प्रशासनिक सुधार।
- एक प्रभावशाली लोकपाल बनाना; साथ ही साथ इ—ग्राम और विश्वग्राम कार्यक्रम चालू करना।
- अदालतों की संख्या दुगुनी करने का लक्ष्य हासिल करना व फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करना।

सरकार का दर्शन - ‘सबसे पहले भारत’

एकमात्र धर्मग्रन्थ - ‘संविधान’

एकमात्र शक्ति - ‘जनशक्ति’

एकमात्र प्रार्थना - ‘जनता की भलाई’

एक रास्ता - ‘सबका साथ-सबका विकास’

हमारा संकल्प

पारदर्शी सरकार, जवाबदेह सरकार

जनकेंद्रित और जनप्रेरित नीतियां

भाजपा लाओ
देश बचाओ।



अबकी बार
मोदी सरकार।